भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः †5443

उत्तर देने की तारीख 25 मार्च, 2026 (बुधवार)

04 चैत्र, 1948 (शक)

प्रश्न

बाढ़ नियंत्रण के लिए एनईएसआईडीएस और पीएम-डिवाइन

†5443. **मोहम्मद रकीबुल हुसैनः**

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का बार-बार आने वाली बाढ़ और बड़े पैमाने पर भूमि, आजीविका और सार्वजनिक अवसंरचना के नुकसान को देखते हुए असम में बाढ़ प्रबंधन, कटाव नियंत्रण और नदी तट संरक्षण उपायों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो बाढ़ नियंत्रण और नदी तटों की सुरक्षा के लिए उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) और उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) सहित उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए उक्त राज्य सरकार अथवा कार्यान्वयन एजेंसियों को कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई है;

(घ) कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और पूरी की गई, चल रही और विलम्ब से चल रही परियोजनाओं का और विलम्ब यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ) जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी स्कीमें तैयार और लागू की जाती हैं। केंद्र सरकार संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है।

केंद्र सरकारबाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी उपाय, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव-रोधी उपाय आदि से संबंधित कार्यों के लिएपूर्वोत्तर क्षेत्र सहित विभिन्न राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" नामक एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

एफएमबीएपी के 'बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम घटक' के तहत असम में कुल 142 परियोजनाएँ शामिल की गई हैं, जिनमें से 111 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, जिनसे लगभग 7.36 लाख हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से सुरक्षा मिल रही है और लगभग 174.52 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है। एफएमबीएपी की शुरुआत से लेकर मार्च 2025 तक, असम सरकार को कुल 1582.54 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने "ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप का बचाव" नामक एक परियोजना को सहायता प्रदान की हैऔर 207 करोड़ रुपये की लागत से यह कार्य पूरा किया गया है।

उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) की स्कीमों के तहत, असम में 33.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बाढ़ प्रबंधन, कटाव नियंत्रण और नदी तट सुरक्षा के उपायों से संबंधित 6 अन्य परियोजनाओं को भी वित्तपोषित किया गया है। इन परियोजनाओं की सूची **अनुबंध-ए** में दी गई है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, असम में आर्द्रभूमियों की जल-धारण क्षमता को बढ़ाने तथा बाढ़ और कटाव के जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से एनईएसएसी द्वारा चिन्हित लगभग 5,900 वर्ग किलोमीटर तथा असम रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर द्वारा प्रलेखित 3,500 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैली आर्द्रभूमियों के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार का कार्य शुरू किया गया है।

*****

अनुबंध-ए

एनईसी की स्कीमों के तहत असम में समर्थित बाढ़ प्रबंधन, कटाव नियंत्रण और नदी तट संरक्षण उपायों से संबंधित परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)
1	असम के धेमाजी ज़िले में जियाधल नदी का नियंत्रण - चरण-I	14.94
2	असम में जनाली नदी के कटाव से रायमोना गाँव और उसके आस-पास के क्षेत्र की सुरक्षा	3.74
3	कोकराझार ज़िले में पेकुआ नदी के कटाव से रानीपुर और उसके आस-पास के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कटाव-रोधी उपाय	3.43
4	बाक्सा ज़िले(असम)में पोमरा नदी के दोनों किनारों पर अलग-अलग हिस्सों में कटाव-रोधी उपाय	2.28
5	कोकराझार (असम) में गंगिया नदी के कटाव से उमा नगर के ऊपरी हिस्से के गाँवों और उनके आस-पास के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कटाव-रोधी उपाय	4.05
6	बाक्सा ज़िले (असम) में दारंगा नदी के किनारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न हिस्सों में कटाव-रोधी उपाय	4.96
	कुल	**33.40**